आमोखस व मिडिया की खबरों व प्रथम समाचार पत्र

RNI No. UPHIN/2012/47484

जननायक सम्राट

बर्ष :13 अंक :339 पृष्ठ -4 दिनांक 13 दिसम्बर 2024 दिन शुक्रवार

राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर बिफरी बीजेपी

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा राहुल गांधी उलूल —जलालू हरकत करते रहते हैं

उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में चार साल पहले हुए रेपकांड के पीड़ितों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिले का दौरा करने वाले हैं. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर बिफर गए हैं. राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आये दिन राहुल गांधी उलूल ——जलालू हरकत करते रहते हैं. राहुल गांधी दिग्भ्रमित हैं. वह पूरी तरह से डिरेल हो चुके हैं. हाथरस मामले को सीबीआई देख रही है. एक ओर जहां प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो वहीं कांग्रेस नेता राज्य को दंगों और हिंसा की आग में झोकना चाहते हैं. इसके अलावा राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं. राहुल गांधी पर तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को ही विश्वास नहीं है. जॉर्ज सोरोस के साथ लगातार कांग्रेस का कनेक्शन जुड़ रहा है.क्या है पूरा मामला?बता दें हाथरस जिले के बहुचर्चित हाथरस बिटिया कांड के पीड़ित परिवार को सरकार की घोषणा के मुताबिक सरकारी आवास तथा नोकरी नहीं मिली है .इन घोषणाओं को पूरी करने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है.अलवत्ता इस केस में दो मार्च 2023 को कोर्ट का फैसला हो चुका है. विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट की अदालत ने इस मामले में आरा. `पी 4 युवकों में से 3 को बरी कर दिया था और एक आरोपी संदीप को आजीवन कारावास तथा 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी.इस फैसले के बाद से बिटिया पक्ष संतुष्ट नहीं है.

बिटिया पक्ष की वकील का कहना था कि वह इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे. इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है.तब बिटिया की भाभी ने भी कोर्ट के निर्णय पर संतुष्टि नहीं जताई थी. उसका कहना था कि वह चारों की सजा पर ही संतुष्ट होंगे और मृतका की अस्थियों का विसर्जन तभी करेंगे.बिटिया के परिजन भी इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील कर चुके हैं.14 सितंबर 2020 को हाथरस के गांव में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और उसे जान से मारने की कोशिश हुई थी .इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को अपना दम तोड़ दिया था इस मामले के गांव के चारों आरोपी युवक जेल भेजे गए थे. सीबीआई ने मामले की जांच करके चारों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी.जिस पर सुनवाई के बाद यह निर्णय आया था . अलबत्ता सीआरपीएफ की टुकड़ी रोजाना की तरह परिवार की सुरक्षा में रहती है . पीड़ित परिवार घटना के बाद से ही गांव के बाहर सरकारी आवास और सरकारी नौकरी की मांग कर रहा था लेकिन शासन की ओर से अभी तक परिवार को यह मदद नहीं दी गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी की जमानत पर सुनवाई टली गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है FIR

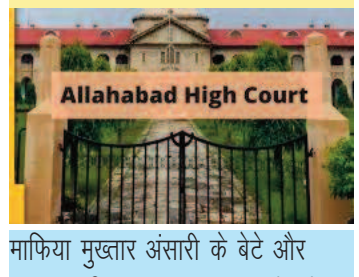

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में अदालत न बैठने के चलते सुभासपा विधायक के मामले में सुनवाई टली है. अब अगले हफ्ते 18 दि. संबर को सुभासपा विधायक के मामले की सुनवाई होगी. इस मामले में जमानत अर्जी पर यूपी सरकार पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुकी हैयूपी सरकार के जवाब पर अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपना रि. ज्वांइडर कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं. इस मामले में अब सभी पक्षों का जवाब दाखिल हो चुका है. अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी–अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे. दरअसल, अब्बास अंसारी के खिलाफ 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कर्वी थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआ. ईआर दर्ज हुई थी.चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अवैध तरीके से मुलाकात और जेल कर्मियों को धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी. तब इस मामले में अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 4 हफ्ते में हाईकोर्ट को जमानत अर्जी तय करने का निर्देश दिया था. जबकि हाईकोर्ट में यह मामला पहले से लंबित है.इस मामले में मिल चुकी है जमानत अक्टूबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा था कि निचली अदालत ऐसी शर्तें लगाएगी, जिससे आरोपी गवाहों को प्रभावित न कर सकें या सबूतों से छेड़छाड़ न कर सकें. ईडी ने तीन अलग–अलग एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी. पहले आपराधिक मामले में यह आरोप लगाया गया था कि एक निर्माण कंपनी के भागीदारों ने रिकॉर्ड में हेराफेरी करके सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया था. दूसरी एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से स्कूल बनवाने के लिए पैसे लिए थे, जबकि स्कूल नहीं बना और जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है.

बेंगलुरू में यूपी निवासी अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में पुलिस जौनपुर पहुंची

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अतुल सुभाष के आत्महत्या के मामले की जांच करने पुलिस जौनपुर पहुंची है. इससे पहले निकिता सिंघानिया के परिजनों में से मां और बेटे उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज पहुंचे है. दावा है वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर सकते हैं. हालांकि अभी तक इस आशय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बुधवार देर रात लगभग साढ़े 11 बजे घर से निकिता की मां और उनके भाई अनुराग सिंघानिया भाग गए. दोनों बेंगलुरु पुलिस की टीम से बच कर निकल गएबता दें केस की आरोपी और निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया देर रात घर से निकल कर कहीं निकल गईं थीं. उनके साथ उनका बेटा अनुराग सिंघानिया भी चुपके से घर से निकल गया. इस दौरान पूछे जाने पर भी निशा सिंघानिया ने कैमरे पर कुछ नहीं बोला. बस वो बाइक पर बैठ कर निकल गईं.इन सबके बीच इंजीनियर अतुल सुभाष के परिवार ने उसके लिए न्याय और उसका उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने वैवाहिक जीवन में लंबे समय से तनाव, उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों तथा उसकी पत्नी, उसके ससुराल वालों और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा प्रताड़ित किए जाने का विस्तृत विवरण दिया है.सुभाष के भाई ने क्या कहा? सुभाष के भाई विकास ने कहा, श्मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को न्याय मिले. मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया हो जिसके जरिए पुरुषों को भी न्याय मिल सके. मैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूं जो विधिक पद पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह जारी रहा तो लोग न्याय की उम्मीद कैसे कर पाएंगे

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग, खिड़कियों के शीशे तोड़ कूदे यात्री

उत्तरप्रदेश आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह तेज रफ्तार बस में आग लग गई। लपटों ने जैसे ही बस को घेरा तो चालक और परिचालक कूदकर भाग निकले। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। किसी ने गेट से तो किसी ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में अंबाला से सवारी लेकर बिहार जा रही डबल डेकर बस में आग लग गई। लखनऊ एक्सप्रेस–वे के किलोमीटर 21 पर हुए इस हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। खिड़कियों के शीशे तोड़कर यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। पुलिस के मुताबिक बृहस्पतिवार सुबह 6रू15 की करीब पटियाला अंबाला से बिहार लगभग 60 सवारी लेकर जा रही डबल डेकर बस जैसे ही थाना फतेहाबाद क्षेत्र की सीमा में लखनऊ एक्सप्रेस–वे के किलोमीटर–21 पर पहुंची तो अचानक टायरों में आग लग गई। इस दौरान ड्राइवर के द्वारा बस को रोक दिया गया। जानकारी से बस में चीख पुकार मच गई। बड़ी मुश्किल से सवारियों ने शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई।. जानकारी पर यूपीड़ा की टीम और फते. हाबाद पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ पहुंच गई। आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग में बस के अंदर रखा यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। चौकी इंचार्ज लुहारी पृथ्वी सिंह ने बताया कि यात्रियों के द्वारा बताया गया है कि टोल प्लाजा से पांच किलोमीटर पहले टायरों में आग लगने की सूचना की जानकारी हुई थी, तभी बस ड्राइवर से बस रोकने को कहा गया था, लेकिन बस ड्राइवर के द्वारा बस को नहीं रोका गया है। यात्रियों की शिकायत के बाद पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।

योगी सरकार की मुश्किल बढ़ाएगी कांग्रेस, बड़े आंदोलन की तैयारी

उत्तरप्रदेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई राज्य में बड़े आंदोलन की तैयारी में है. यह जानकारी रामपुर खास से कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने एक प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने कहा कि18 तारीख को यूपी विधानसभा को सत्र के दौरान घेराव का निर्णय लिया है. आज यूपी की सरकार हर विषय पर फेल है चाहे वह किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, निजीकरण की एक विभीषिका आज चुनौती बनकर देश के सामने खड़ी है. मिश्रा ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय है हर मामले में सरकार असफल है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विधानमंडल दल के नेता के रूप में लगातार हमने प्रयास किया कि विधानसभा के अंदर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें सरकार का ध्यान आकर्षित करें मामले पर चर्चा करें पर यह किसी से छुपा नहीं है कि लगातार यूपी विधानसभा में सरकार किसी भी तरीके पर नजर रखी जाएगी।हालांकि, वर्ष 2019 में इसरो ने कुंभ की तस्वीरें ली थीं। तब 16 जनवरी को इसरो द्वारा कुंभ क्षेत्र की दो तस्वीरें जारी भी की गई थीं। उन तस्वीरों में संगम क्षेत्र और तट पर जमा लाखों श्रद्धालु दिखे थे। तब इसरो ने अपने ट्विटर अकाउंट (अब एक्स) से फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि कुंभ मेला–2019 की दो तस्वीरें रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कार्टोसैट–2 से ली गई हैं, जो कुंभ के क्षेत्र को दिखा रही हैं।सरो द्वारा की चर्चा से दूर भागती है किसी भी चीज का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है यह कि हम सरकार की जवाब देही उन विषयों पर तय करें इन विषयों पर यूपी की जनता ने उन पर विश्वास किया है और उनको चुनकर भेजा है.बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर मिश्रा ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि पब्लिक सेंटर में चाहे वह बिजली और यह सब सरकार की जिम्मेदारी है यह लाभ का विषय नहीं हो सकते पर क्योंकि सरकार की प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं बल्कि पूंजीपतियों को कमाई कराना है और इसीलिए लगातार हर क्षेत्र में निजीकरण एक विभीषिका बनकर आगे बढ़ रही है.मिश्रा के मुताबिक दूसरा विषय किसानों का है. उन्होंने कहा कि आज खाद की कितनी बड़ी किल्लत है ,डीएपी का दाम बढ़ रहा है और वजन जारी की गई उन तस्वीरों में गंगा और यमुना का संगम दिखने के साथ ही उनके रंग का अंतर भी साफ दिख रहा था। हालांकि, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में यमुना का जल काला और गंगा जल हल्का काला दिख रहा था। यमुना में चल रही नावें भी तस्वीर में कैद हुई थीं। इतना ही नहीं गंगा में बनाए गए पांटून पुल भी सेटेलाइट इमेज में लकीर जैसे दिखे थे। इसके अलावा ओडी कम हो रहा है और इन सब के बावजूद खाद्य मुहैया नहीं हो रही है हमने इस विषय को लगातार विधानसभा में दिखाने का प्रयास किया पर सरकार के हिसाब से सब ठीक है. गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, जो पैसा सरकार ने दिया वह मिल मालिकों को दिया किसानों को नहीं दिया. आज यूपी में किसानों की लागत कहीं ज्यादा है और कमाई बहुत कम है. प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता ने कहा कि तीसरा महत्वपूर्ण विषय युवाओं की बेरोजगारी का है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 100 में से पचासी युवा बेरा. `जगार हैं. आज सरकार युवाओं को नौ. करी नहीं दे पा रही पर उनको लाठियां जरूर दे रही है गंभीर धाराओं मुकदमे ले रही है. इस सरकार में 14 पेपर लिखकर रिकॉर्ड काम किया है. 69000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के कहने के बावजूद सरकार को आरक्षण देना था उसपर कुछ नहीं हुआ.
फोर्ट, नया यमुना पुल, संगम के आसपास की वाटर बैरिकेडिंग आदि सब कुछ सेटेलाइट इमेज में दिखी थी।2019 के मुकाबले इसरो अब तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। ऐसे में उम्मीद है कि महाकुंभ–2025 के दौरान इसरो की सेटेलाइट द्वारा महाकुंभ से जुड़ी बेहतरीन तस्वीरें जारी की जाएंगी। हालांकि, सुरक्षा की दृष्टि से इसरो के बारे में मेला प्रशासन अभी कुछ भी कहने से बच रहा है।

अंतरिक्ष से भी दिखेगा महाकुंभ, इसरो की सेटेलाइट लेंगी तस्वीरें

महाकुंभ मेला क्षेत्र की विशेष निगहबानी भी की जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। खास बात यह है कि इस बार सेटेलाइट से भी महाकुंभ मेले पर नजर रखी जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का भागीदार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भी बनेगा। बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष से महाकुंभ की तस्वीरें इसरो की सेटेलाइट से ली जाएंगी। सभी स्नान पर्वों के दौरान सेटेलाइट से महाकुंभ मेला क्षेत्र की विशेष निगहबानी भी की जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। खास बात यह है कि इस बार सेटेलाइट से भी महाकुंभ मेले

बांग्लादेशी मुस्लिम क्या मजहब देखकर भारत और पाकिस्तान को पसंद-नापसंद करते हैं?

भारत के साथ बढ़ती दूरियों के बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं. मोहम्मद यूनुस सरकार ने कुछ दिन पहले ही चीनी, असलहों का ऑर्डर दिया और साथ ही पाकिस्तानियों को वीजा के लिए जरूरी शर्तों में भी रियायात दे दी. दोनों देशों को लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार का जो रुख है, क्या बांग्लादेशी भी उसी तरह सोच रहे हैं? इसे लेकर बांग्लादेश में एक सर्वे किया गया और इसमें बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. बांग्लादेशियों के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही बराबर हैं. यहां तक कि बांग्लादेशी मुस्लिमों की नजरों में भी दोनों मुल्कों की इमेज में कोई अंतर नहीं है, दोनों के लिए ही वहां सकारात्मक राय है. वीओए बांग्ला ने शनिवार (7 दि. संबर, 2024) को एक सर्वे रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बांग्लादेशियों से भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और म्यांमार को लेकर सवाल किए गए और 1 से 5 के स्केल पर रेटिंग देने के लिए कहा गया. 1 और 2 रेटिंग देने का मतलब है कि आप उस देश को पसंद करते हो, जबकि 4 और 5 रेटिंग का मतलब ना पसंद है.किस देश को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं बांग्लादेशी? सर्वे में शामिल 59 फीसदी लोगों ने पाकिस्तान को पसंद किया, जबकि 53.6 फीसदी बांग्लादेशियों को भारत पसंद है. बांग्लादेश के लोगों का सबसे पसंदीदा देश अमेरिका है, जिसे 68.4 फीसदी लोग लाइक करते हैं. उसके बाद चीन 66 फीसदी लोगों की पसंद के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि रूस तीसरे और ब्रिटेन चौथे नंबर पर है. रूस को 64 फीसदी और ब्रिटेन को 62.7 फीसदी लोग पसंद करते हैं. सबसे कम लोगों ने म्यांमार को पसंद किया है. इसे लाइक करने वाले सिर्फ 24.5 फीसदी लोग हैं, जबकि डिस्लाइक करने वाले 59.1 फीसदी हैं.भारत और पाकिस्तान में कौन ज्यादा पसंदीदा मुल्क?भारत और पाकिस्. तान में कौन सा देश बांग्लादेशियों को ज्यादा नापसंद है, तो इसमें भारत को ज्यादा वोट मिले. पाकिस्तान को नापसंद करने वाले 28.5 फीसदी लोग हैं, जबकि 41.3 फीसदी ने भारत को नापसंद किया. लाइक स्केल पर देखें तो भले पाकिस्तान को पसंद करने वाले ज्यादा हैं, लेकिन अगर उम्र और लिंग के आधार पर देखेंगे तो आंकड़ा एकदम अलग है. यानी युवा ज्यादा पाकिस्तान को पसंद करते हैं, लेकिन वयस्कों ने भारत को चुना. इसी तरह पुरुषों ने पाकिस्तान को लाइक किया तो महिलाओं ने

भारत को. वहीं, बांग्लादेशी मुस्लिमों ने भी भारत और पाकिस्तान को लगभग बराबर ही रेटिंग दी है. हालांकि, नॉन मुस्लिम जैसे हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों के आंकड़ों में दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा फर्क है.कितने बांग्लादेशी मुस्लिम भारत को करते हैं लाइक?बांग्लादेशी मुस्लिमों की बात करें तो 50.7 फीसदी भारत को और 60.1 फीसदी पाकिस्तान को पसंद करते हैं. इस आंकड़े पर गौर करें तो अंतर बहुत कम है. इसका मतलब वहां की जनता ने मजहब देखकर वोट नहीं किया अगर ऐसा होता तो शायद पाकिस्तान को पसंद करने वाले 90 फीसदी या उससे भी ज्यादा हो सकते थे. 44.2 फीसदी मुस्लि. मों ने भारत को नापसंद किया है, जबकि 4.2 फीसदी गैर-मुस्लिमों ने भी नापसंद किया है. वहीं, 90.1 फीसदी नॉन-मुस्लिम भारत को पसंद करते हैं और 44.1 फीसदी पाकिस्तान को.पाकिस्. तान को पसंद करने वाले कितने बा. ंग्लादेशी?18 साल से 34 साल की उम्र तक के 47.8 फीसदी लोग भारत को पसंद करते हैं और 49.3 फीसदी नापंसद करते हैं. वहीं, 35 साल से ज्यादा उम्र की 59.8 फीसदी आबादी भारत को पसंद करती है, जबकि 35 फीसदी पसंद नहीं करती है. 52 फीसदी पुरुषों ने और 55.3 फीसदी महिलाओं ने भारत को पसंद किया, जबकि 64.4 फीसदी पुरुषों और 53.2 फीसदी महिलाओं ने पाकिस्तान के लिए वोट किया.

ईरान में सख्त हिजाब कानून, ड्रेस कोड का उल्लंघन किया तो मिलेगी सीधा मौत की सजा

ईरान अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है. बता दें कि ईरान ने हाल ही में हिजाब को लेकर नए कानून लागू किए हैं जो विवाद का कारण बन गए हैं. इन कानूनों के अनुसार अगर महिलाएं हिजाब के नियमों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें मौत की सजा तक दी जा सकती है. नए कानून के अनुच्छेद 60 के तहत दोषी महिलाओं को जुर्माना, कोड़े की सजा या कठोर जेल की सजा हो सकती है. अगर कोई महिला एक से ज्यादा बार इस कानून का उल्लंघन करती है तो उसे 15 साल तक की जेल या फांसी की सजा का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा ईरानी अधिकारियों ने एक विवादास्पद हिजाब क्लीनिक खोलने का भी ऐलान किया है जिसका उद्देश्य हिजाब के नियमों का पालन कराना है.विदेशी मीडिया और संगठनों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवा. ईइंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में यदि कोई विदेशी मीडिया या संगठन हिजाब विरोधी विचारों को बढ़ावा देता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 12,500 पाउंड तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. साथ ही अगर कोई महिला की गिरफ्तारी को रोकने या इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है तो उसे भी सजा दी जाएगी. ईरान की सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ऐसे व्यक्तियों को सीधे जेल में डाला जा सकता है. 2022 में हिजाब कानून का महिलाओं ने किया था विरोध 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया था. इसके बावजूद 2022 में इन हिजाब कानूनों के खिलाफ देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. इस विरोध का मुख्य कारण 16 सितंबर 2022 को 22 वर्षीय महसा अमिनी की पुलिस हिरासत में मौत थी. जानकारी के मुता. बिक महसा अमिनी को मोरल पुलिस ने ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसकी मौत के बाद देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे. इन घटनाओं के बाद सरकार ने कई विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए हजारों लोगों को गिरफ्तार किया था और अब दो साल बाद सरकार ने पहले से भी सख्त हिजाब कानून लागू कर दिए हैं. नए कानूनों के खिलाफ छिड़े वैश्विक विरोध ईरान में लागू किए गए ये नए कानून न केवल देश के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विवाद का कारण बने हैं. मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक समुदाय ने इन कानूनों को महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए विरोध जताया है. उनका कहना है कि ये कदम महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन करता है. हालांकिइस पर ईरान सरकार का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य समाज में हिजाब की संस्कृति की पवित्रता बनाए रखना है और महिलाओं को एक विशेष प्रकार के ड्रेस कोड को अपनाने के लिए प्रेरित करना है.

हम भी मंदिरों के नीचे बौद्ध धरोहर की खोज के लिए सर्वेक्षण कराने की याचिका करेंगे दायर- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

अजमेर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अजमेर की दरगाह पर किए दावे को आधारहीन बताकर स्थानीय अदालत के नोटिस जारी करने पर अचरज जताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी व स्थानीय खादिमों ने पत्रकार वार्ता के दौरान संयुक्त रूप से बयान जारी किया। बयान में बताया कि प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट 1991 में 15 अगस्त 1947 की पूजा स्थल की स्थिति को चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों की मस्जिदों सहित अजमेर की दरगाह पर दावे किए जा रहे हैं।ऐसे विषय देश में अस्थिरता और अशांति का कारण बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट से इसमें हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। बुधवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना शाह फजलुर्रहीम मुजदिदी, प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास, सैयद सरवर चिश्ती, सैयद गफ्फार हुसैन काजमी, सैयद अब्दुल हक, सैयद शारिब संजरी, सैयद शमीमी उस्मानी ने संबोधित किया।याचिका संविधान की परीक्षा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय महासचिव यासमीन फारूकी ने दायर वाद को संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के लिए चुनौती बताया। उन्होंने कहा, 'यह याचिका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान की परीक्षा है। ख्वाजा साहब के करोड़ों अनुयायी उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र और बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजरत्न अंबेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो हम भी मंदिरों के नीचे बौद्ध धरोहर की खोज के लिए सर्वेक्षण कराने की याचिका दायर करेंगे।देश की एकता पर हमलाएसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी ने 800 साल पुरानी दरगाह की ऐतिहासिक अहमियत को रेखांकित करते हुए कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह दरगाह हमेशा से धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक रही है।

भारी बारिश के पूर्वानुमान, तमिलनाडु के इन 11 जिलों में स्कूल बंद, IMD ने जारी किया अलर्ट

तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका के चलते 11 जिलों में सभी स्कूल बंद रहेंगे। चेन्नई, विल्लुपुरम, तंजावुर, मयिलादुथुराई, पुदुक्कोट्टई, कुड्डालोर, डिंडीगुल, रामनाथपुरम, तिरुवरुर, रानीपेट और तिरुवल्लूर जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।गुरुवार को भारी बारिश की आशंका के चलते तमिलनाडु के 11 जिलों में सभी स्कूल बंद रहेंगे। चेन्नई, विल्लुपुरम, तंजावुर, मयिलादुथुराई, पुदुक्कोट्टई, कुड्डालोर, डिंडीगुल, रामनाथपुरम, तिरुवरुर, रानीपेट और तिरुवल्लूर जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस बीच, आज सुबह थूथुकुडी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई।भारत मौसम विज्ञान (प्डक्) विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने वेल्लोर, पेरम्बूर, सेलम, नमक्कल, शिवग. ंगा, मदुरै और डिंडीगुल में हल्की गरज के साथ मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग ने अपनी नवीनतम विज्ञप्ति में कहा कि थूथकुडी, तेनकासी और तेनी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है।इन जगहों पर हल्की बारिश की सम्भावना इससे पहले, आईएमडी ने कहा कि मध्य पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले दो दिनों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में हल्की से लेकर अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। रविवार को अपने नवीनतम पूर्वानुमान में, आईएमडी ने 9 दिसंबर से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शीत लहर की भविष्यवाणी की। शीत लहर की होगी शुरुआतIMD की एक विज्ञ. प्ति के अनुसार, 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक पश्चिमी राजस्थान में शीत लहर की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 दिसंबर से शीत लहर की स्थिति रहेगी। आईएमडी शीत लहर की स्थिति को किसी दिए गए स्थान के लिए सामान्य जलवायु मूल्यों की तुलना में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट के रूप में परिभाषित करता है।

जिंदगी की जंग हार गया आर्यन, 56 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

दौसा। जिले के पापड़दा थाना क्षेत्र के कालीखाड़ गांव में 3 दिन से बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम आर्यन को बुधवार देर रात करीब पौने बारह बजे बाहर निकाल लिया गया है। मौके से तुरन्त बच्चे को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम युक्त एंबुलेस से दौसा जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां ईसीजी के बाद चिकित्सकों में बालक को मृत घोषित कर दिया। बच्चे को बाहर निकालने के लिए करीब 56 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बालक के मौत की खबर सुनकर माहौल गमगीन हो गया।जानकारी के अनुसार एनडीआरएफ की टीम ने बुधवार रात करीब 10 बजे एक बार फिर अम्ब्रेला उपकरण, रिंग उपकरण और रस्सी से बंधी हुई तीनों रॉड को बोरवेल में डाला और तीनों को एक साथ खींचते हुए मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाल लिया। इससे पहले बुधवार को दिनभर बोरवेल से करीब 6 फीट की दूरी पर ही 155 फीट का नया सुरंगनुमा गड्ढा खोदा जा रहा था। गौरतलब है कि आर्यन सोमवार दोपहर 3 बजे खेलते-खेलते खुले बोरवेल में गिर गया था। इसके बाद आर्यन को निकालने के लिए लगातार तीन दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा था, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका।बता दें कि सोमवार दोपहर करीब 3 बजे बोरवेल में गिरे पांच वर्षीय आर्यन मीना को निकालने के लिए दो तरह से ऑपरेशन कामयाब नहीं होने के बाद बुधवार को तीसरे तरीके से प्रयास किया गया। पाइलिंग मशीन से तड़के करीब तीन बजे सुरंगनुमा करीब चार फीट का गोलाकार गड्ढा खोदना शुरू किया गया। करीब 110 फीट की खुदाई के बाद मशीन में सुबह साढ़े दस बजे तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद दिनभर खुदाई का काम बंद रहा। शाम को शाहपुरा से दूसरी पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंची और रात सात बजे फिर से खुदाई चालू की गई। इससे पूर्व जेसीबी व एल एंड टीम मशीन से बोरवेल के समीप खोदे जा रहे गड्ढे का कार्य बंद कर दिया गया। सवाईमाधोपुर से मंगवाई पाइलिंग मशीन से एक घंटे में करीब 20 फीट तक खुदाई की गई। ऐसे में संभावना थी कि दोपहर 12 बजे तक 160 फीट खुदाई हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मशीन खराब हो गई। यह गड्ढा बोरवेल से करीब 5 फीट दूर किया गया।

कलक्टर की मौजूदगी, सांसद-विधायक भी पहुंचे मौके पर जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार व एएसपी दिनेश अग्रवाल सहित कई अधिकारी लगातार तीन दिन से मौजूद रहे। वहीं सांसद मुरारीलाल मीना तडके करीब तीन बजे घटनास्थल पर पहुंचे। इनके अलावा लालसोट विधायक रामविलास मीणा, बांदीकुई विधायक भाग. चंद टाकड़ा, सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल, भाजपा नेता जगमोहन मीणा भी मौके पर पहुंचे। बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण, पुलिस ने रोका पाइलिंग मशीन से शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने तथा आर्यन की सलामती के लिए बुधवार को हजारों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा रहे। लोग पेड़ पर चढ़ गए। ऐसे में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया तथा जनप्रतिनिधियों ने भी बार-बार लोगों से दूर होने की अपील की। एएसपी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि आसपास के जिलों से भी लोग यहां आने की सूचना मिली। इस पर क्षेत्र में चेकपोस्ट लगाकर बाहरी लोगों को यहां आने से रोका गया।

400 क्विंटल फूलों से होगा च्ड डवकप का भव्य स्वागत, मंगाए गए 15 किस्मों के गुलाब

प्रधानमंत्री मोदी कल प्रयागराज में 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभा. रंभ करेंगे। इस दौरान उनका स्वागत 400 क्विंटल फूलों से किया जाएगा।13 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे। इस दौरान वह जनता को सात हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस मौके पर प्रयागराज में चार सौ क्विंटल फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, जिसके लिए 15 किस्म के गुलाब मंगाए गए हैं।कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 32 प्रजातियों के फूल व जिप्सो व बेबीज ब्रीथ जैसे विदेशी फूल भी वातावरण को महकाएंगे। इन फूलों से हनुमान मंदिर और अक्षयवट कॉरिडोर को आकर्षक रूप दिया जाएगा। दो दिन पहले ही तीन ट्रक फूल संगम तट पर लाए गए हैं। 15 किस्मों में लाल, सफेद, पीला, बादामी, रानी आदि रंगों के गुलाब शामिल हैं।कोलकाता से मंगवाई गई गेंदे के फूल की दो किस्में इसके अलावा, कोलकाता से गेंदे के फूल की दो किस्में आई हैं। इसी तरह लिली व आर्किड के फूल भी मंगाए गए हैं। यही नहीं कई विदेशी प्रजाति के फूल भी शामिल हैं जिनकी कीमत 600 से 700 रुपये प्रति वंच है। इनमें कार्नेशन स्टार एनाइस, बेबीज ब्रीथ, जिप्सो के अलावा डेजी आदि शामिल हैं।फूलों के साथ ही कई तरह के पत्ते भी मंगाए गए कारीगरों ने बताया कि इन फूलों को कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कई प्रजातियों के फूलों को पहले से बुक कराकर मंगाया गया है। सजावट के लिए फूलों के साथ ही कई तरह के पत्ते भी मंगाए गए हैं। इनमें मनोकामना, ताल पत्ता, यार्चा, पाम व बॉल एस्परैगस, द्रसिनिया जैसे पौधों के पत्ते शामिल हैं। जिन्हें सजावट में इस्तेमाल किया जाएगा।पीएम के कार्यक्रम के पहले मंच को फूलों से सजाने के लिए करीब 250 मजदूर पिछले चार दिनों से रात-दिन काम कर रहे हैं। संगम नोज पर बने पंडाल में फूलों से स्वागत द्वार व छावनी आदि बनाने का काम चल रहा है। ये कारीगर लखनऊ की एक फ्लावर डेक. ोरेशन एजेंसी से बुलाए गए हैं जो मूलतः पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।

अब पीने के लिए भी दिखाना पड़ेगा ID प्रूफ

दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्तराओं को निर्देश जारी किए हैं कि वे शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल का अनुपालन सुनिश्चित करें। संचालकों को अब सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी का उपयोग करके ग्राहकों की उम्र सत्यापित करनी होगी। यह निर्देश आबकारी विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के जवाब में आया है, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों में कम उम्र के लोगों के शराब पीने के मामले पाए गए।अधिकारियों ने खुलासा किया कि 25 वर्ष से कम उम्र के कुछ ग्राहक उम्र की आवश्यकता को पूरा करने का दिखावा करते हुए शराब पीते पाए गए। नाबालिगों को शराब परोसने के लिए आबकारी लाइसेंसधारियों के खिलाफ भी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके बाद विभाग ने इन उल्लंघनों की समीक्षा की। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत, किसी भी व्यक्ति, लाइसेंसधारी विक्रेता, या उनके कर्मचारियों या एजेंटों के लिए 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचना या वितरित करना अवैध है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या दूसरों के लिए। विभाग ने लाइसेंस धारकों को जारी एक परिपत्र में इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "होटल, क्लब, रेस्तरां के सभी लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के माध्यम से उम्र की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है।

श्री भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा एमएस एक्ट-2013 के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्किट हाउस में की गई मण्डलीय बैठक

मण्डल भर में मलिन बस्तियों में शिविर आयोजित

अलीगढ़ मा0 सदस्य सेन्ट्रल मॉनिटरिंग कमेटी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं पूर्व मंत्री उत्तराखण्ड श्री भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा सर्किट हाउस सभागार में एमएस एक्ट–2013 के सफल क्रियान्वयन के लिए मण्डलीय समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने बताया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढोने) को रोकने और पुनर्वास के लिए साल 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन ऐंड रिहैबिलिटेशन एक्ट लाया गया था। इस अधिनियम के तहत हाथ से मैला ढोने के कार्य पर पूर्णतः रोक लगाते हुए इसे संज्ञेय अपराध माना गया है और इस कार्य में लगे व्यक्तियों व उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, ऋण और आवास प्रदान कर पुनर्वासन की व्यवस्था की गई है। जिलों में एमएस एक्ट–2013 के तहत जिला मजिस्ट्रेट सफाई कर्मियों के पुनर्वासन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि मण्डल के सभी जिलाधिकारी इसे धरातल पर मूर्त रूप देंगे।मा0 सदस्य ने कहा कि हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वासन के लिए मा0 सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र व प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद भी कई जिलों से विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मा0 प्रधानमंत्री जी स्वच्छाग्राहियों के सम्मान एवं उत्थान के लिए संवेदनशील हैं और उन्होंने कुम्भ के समापन के पश्चात पैर भी धोए और कारोना के दौरान इन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित किया। उन्होंने उप निदेशक समाज कल्याण आनन्द को निर्देशित किया कि मण्डल भर में मलिन बस्तियों में शिविर आयोजित कर समाज के पात्र एवं जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वित्त विकास निगम द्वारा वाहन के क्रय के लिए 85 प्रतिशत धन. राशि वहन करती है, समाज के पात्र युवाओं को इसका लाभ देना सुनिश्चित करें।उन्होंने जिलास्तरीय अस्पतालों में ठेके एवं आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए सफाई कर्मियों की संख्या एवं मानदेय के बारे में समुचित जानकारी न होने पर सीएमओ डॉ0 नीरज त्यागी के प्रति कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए एक सप्ताह में जिले के सभी अस्पतालों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने परिवहन विभाग को वाहनों के परमिट में सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता देने एवं एनआरएलएम को समाज की महिलाओं के समूह गठित कराने के निर्देश दिए।एटूजैड प्लांट में विगत 14 वर्षों से कार्य कर रहे सफाईकर्मी सचिन ने बताया कि अब उनको दूसरी कंपनी में मर्ज कर दिया गया है, परन्तु एटूजैड द्वारा अभी तक उनके ईपीएफ का भुगतान नहीं किया गया है। एएलसी शेर सिंह ने बताया कि इस संबंध में एटूजैड और सफाई कर्मियों के मध्य कई समन्वय बैठक आहुत की गई जोकि बेनतीजा रहीं इस प्रकरण की जांच के लिए अनुमति हेतु मुख्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है। मा0 सदस्य ने नगर निगम समेत सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि बहानेबाजी छोड़ ठेके और आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए सभी कर्मियों को ईपीएफ और ईएसआई का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने एमएस एक्ट के तहत उप निदेशक समाज कल्याण को जिला सर्वेक्षण समिति, जिला अनुश्रवण कमेटी एवं खण्ड स्तरीय कमेटी गठित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि समाज के लोगों के पुनर्वासन में उदासीनता बरतने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।बैठक के अंत में अपर जिलाधिकारी नगर अमित कुमार भट्ट ने मा0 सदस्य को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए मार्गदर्शन एवं निर्देशों के तहत जिले में सफाई कर्मियों को विभागीय अधिकारियों के माध्यम से लाभान्वित कराते हुए उनके पुनर्वासन को सुनिश्चित कराया जाएगा।बैठक में अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, सीएमओ डा0 नीरज त्यागी, एडीपीआरओ मो0 ए0 राशिद, एएलसी शेर सिंह समेत मण्डलीय अधिकारी एवं नगर निकायों के ईओ, सफाई मजदूर संघ अध्यक्ष प्रदीप भण्डारी, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष भाजपा अमरदीप डागौर समेत अन्य जनप्रतिनिधि व सफाईकर्मी उपस्थित रहे।

अधिकारियों को 25 दिसंबर से नई पत्राव लियों को ई-ऑफिस के माध्यम से ही परिचालित करने के दिए निर्देश

अलीगढ़ विकास कार्यों से जुड़े विभागों की पत्रावलियां अब ई–ऑफिस के माध्यम से ही परिचालित की जाएंगी। यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने दिए हैं। वह गुरुवार को विकास भवन सभागार में ई–ऑफिस प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में ई–ऑफिस के माध्यम से शासकीय पत्रावलियों का परिचालन किया जा रहा है। जिलाधिकारी विशाख जी0 की विशेष पहल पर कलैक्ट्रेट कार्यालय में अगस्त माह से ही ई–ऑफिस के माध्यम से कार्य आरंभ हो चुका है। सीडीओ ने सभी विभागीय अधिकारियों एवं पटल सहायकों को निर्देशित किया कि 25 दिसंबर से वह नई पत्रावलियों को ऑफलाइन स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह पत्र निर्गत कर पूर्व में ही निर्देश भी दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने माउस क्लिक कर ई–ऑफिस का भी शुभारंभ किया।ईडीएम मनोज राजपूत ने ई–ऑफिस संचालन के बारे में विकास भवन सभागार में विकास से जुड़े सभी अधिकारियों एवं पटल सहायकों को प्रशिक्षण देते हुए ई–ऑफिस के लिए उपयोग में आने वाले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, डीएससी, ईमेल आईडी, वीपीएन, गूगल इंडिक टूल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि ई–ऑफिस संचालन के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिजिटल सिग्नेचर एवं एनआईसी के सर्वर पर ईमेल आईडी बनवाना अनिवार्य किया गया है, इसके बिना ई–ऑफिस पर कार्य किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि मैपिंग का कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए विकास भवन में सनी चौधरी कनिष्ठ लिपिक को जिम्मेदारी दी गई है। डीडीओ आलोक आर्य ने अधिकारियों एवं पटल सहायकों को समझाया कि कोई भी नया कार्य आ. रंभ करने में कुछ कठिनाई अवश्य ही महसूस होती है, परन्तु दृढ़संकल्प और परिश्रम से बड़ी से बड़ी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर 25 दिसंबर से ई–ऑफिस के माध्यम से ही पत्रावलियों को स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं पटल सहायकों को नसीहत देते हए कहा कि वह प्रशिक्षण में बताए गए बिन्दुओं को अच्छे से आत्मसात करें, ताकि ई–ऑफिस संच. ालन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

डीएम की अध्यक्षता में जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक 19 दिसंबर को

अलीगढ़ जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में जिला गंगा सुरक्षा समिति एवं वृक्षारोपण के संबंध में 19 दिसंबर को अपरान्ह 12:30 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में बैठक आहुत की जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए प्रभागीय निदेशक सामा. जिक वानिकी धनराज मीना ने बताया है कि बैठक में गंगा को निर्मल व अविरल बनाए रखने, महाकुंभ–2025 के लिए कार्ययोजना तैयार किए जाने, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्रियान्वित किए जाने, गंगा समितियों की बैठकों एवं गतिविधियों के सुचारू संचालन और गत वर्षों में कराए गए वृक्षारोपण और जिओ टैगिंग के संबंध में विचार–विमर्श किया जाएगा।

नुमाईश ग्राउंड स्थित शिल्पग्राम में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लगेगी मण्डल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योगी प्रदर्शनी

मण्डल एवं देश–प्रदेश के ग्रामोद्योग अपने उत्पादों की करेंगे बिक्री एवं प्रदर्शन. विभागीय अधिकारी स्टॉल लगाकर योजनाओं की देंगे जानकारी

अलीगढ़ उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मण्डल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योगी प्रदर्शनी का आयोजन 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अलीगढ़ के नुमाईश ग्राउंड स्थित शिल. पग्राम में किया जा रहा है।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजीदा बेगम ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मण्डल स्तरीय प्रदर्शनी में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में पंजीकृत इकाईयों के द्वारा उत्कृष्ट उत्पादों के प्रचार–प्रसार व बिक्री के लिए स्टॉल लगाये जाएंगे, जिसमें समीपवती प्रदेशों की इकाईयों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अनुरोध किया है कि प्रदर्शनी अवधि में अपने विभाग के प्रचार प्रसार एवं पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए स्टॉल लगाएं ताकि प्रदर्शनी में बिक्री को बढ़ावा दिये जाने के साथ–साथ प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को विभाग के कार्यकलापों की जानकारी दी जा सके।

सड़क पार करती महिला को मारी टक्कर, इलाज केदौरान हुई मौत, परिवार में छाया मातम

अलीगढ़ (जननायक सम्राट) सड़क पार करते समय एक वाहन ने महिला को टक्कर मार दी। घायल महिला को उपचार के लिए अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।सड़क पार कर रही महिला को अकराबाद के जीटी रोड पर बीते दिनों वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला की उपचार के दौरान 12 दिसंबर को मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।गांव नगला वक्सी निवासी पिंटू सिंह ने बताया है कि उसकी 35 वर्षीय भाभी कृष्ण कुमारी बीते शनिवार को खेत में कामकाज कर घर वापस लौट रही थीं। सड़क पार करते समय एक वाहन ने उनको टक्कर मार दी। घायल महिला को उपचार के लिए अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया है कि महिला ने अपने पीछे एक बेटा व दो बेटियों को रोते बिलखते छोड़ा है।

सिकंदराराऊ की नुमाइश हुई शुरू

अलीगढ़ हाथरस के सिकंदराराऊ में नुमाइश शुरू हो गई है। कस्बे के वार्षिक आयोजन हिंदू मुस्लिम एकता प्रदर्शनी का 12 दिसंबर को फीता काट और मिष्ठान वितरित कर धूमधाम से शुभारंभ हुआ। नुमाइश एक महीने तक लगेगी, जिसमें मनोरंजन के साथ–साथ घरेलू उपयोग की वस्तुएं मिलेंगी।प्रदर्शनी ठेक. `दार विनोद वार्ष्णेय, शिवम राजू, कन्नू लाला, बाबर सिद्दीकी, पम्मी सिद्दीकी, पप्पू यादव, मोह हारून ने दुकानदारों की मौजूदगी में फीता काट कर नुमाइश का शुरूआत की। आयोजकों ने कहा कि यहां क्षेत्र के लोगों को सस्ते मनोरंजन के साथ उच्च स्तरीय खाद्य पदार्थ मिलेंगे। सुरक्षा के लिए कोतवाली पुलिस ने जगह–जगह बैरियर लगाए हैं। प्रदर्शनी में पुलिस चौकी भी स्थापित की गई है।नुमाइश वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला बड़ा आयोजन है, जिसमें ला. `गों के मनोरंजन के साथ–साथ रोजमर्रा के घरेलू उपयोग की वस्तुएं मिल जाती हैं। नुमाइश में ऊंट की सवारी, गगनचुंबी झूले, चाइनीज नाव, महिलाओं के लिए कप–प्लेट और क्रोकरी का सामान, खेल का सामान उचित दामों में उपलब्ध रहते हैं। खाने में जहां सॉफ्टी, कॉफी, पिज्जा, बर्गर, चाऊमीन आदि स्नेक्स मिलते हैं, वहीं ग्रामीण अंचल का पसंदीदा खजला, पराठा तथा गर्मा–गर्म जलेबी, हलवा भी मिलता है। लोग चाट पकौड़ी का भी आनंद प्रदर्शनी में उठाते हैं।

जेएन मेडिकल कॉलेज चिकित्सक द्वारा वायुमार्ग प्रबंधन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के एनेस्थिसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर विभाग के प्रोफेसर एस मुईद अहमद ने जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 'क्रिटिकल केयर मेडिसिन' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और इसके निदेशक के रूप में डि. फिकल्ट एयरवे कार्यशाला का संचालन किया। डिफिकल्ट एयरवे कार्यशाला में वीडियो आधारित शिक्षाप्रद व्याख्यान, व्यावहारिक प्रशिक्षण और केस चर्चाएं शामिल थीं। उन्होंने एक डिफिकल्ट एयरवे केस का संचालन किया और डि. फिकल्ट एयरवे के प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों पर चर्चा की और मैनिकिन और पशु मॉडल दोनों पर सर्जिकल एयरवे करने के विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन किया। एक व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए, प्रोफेसर अहमद ने आईसीयू में गंभीर रूप से बीमार रोगी के एयरवे प्रबंधन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एयरवे प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि नियमित वैकल्पिक मामलों की तुलना में रुग्णता और मृत्यु दर बहुत अधिक है।

कॉरपोरेट्स के मुनाफे में छप्पड़फार बढ़ोतरी, फिर भी नहीं बढ़ रही कर्मचारियों की सैलरी!

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी ग्रोथ की रफ्तार में आई सुस्ती से अब सरकार ही परेशान हो गई है. कम सैलरी की मार अब देश के विकास पर पड़ने लगी है. हाल ही में देश में अर्थव्यवस्था के विकास के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की कम सैलरी को लेकर भारत सरकार की चिंता इसलिए और भी ज्यादा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा कोई कम नहीं है. इसके बाद भी सैलरी बढ़ने का ग्राफ फ्लैट है. सैलेरी ग्रोथ की रफ्तार के सुस्त पड़ने का असर खपत और डिमांड पर पड़ा है. शहरी खपत लगातार कम हो रही है. मुनाफा बढ़ा 400:, सैलरी ग्रोथ 4: भी नहीं प्रा. इवेट कर्मचारियों की कम सैलरी को लेकर सरकार इसलिए भी टेंशन में है, क्योंकि जुलाई से सितंबर की तिमाही में जीडीपी केवल 5.4 फीसदी बढ़ी. इसके पीछे का बड़ा कारण यह सामने आ रहा है कि 2019 से 2023 के बीच कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे में चार गुना यानी 400 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि इसी दौरान प्राइवेट कर्मचारियों के वेतन चार फीसदी भी नहीं बढ़े हैं. भारत सरकार की ओर से फिक्की और क्वेश कॉर्प लिमिटेड की ओर से तैयार कराए गए आंकड़ों से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, इंजीनियरिंग, मैनुफै. क्चरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो केवल 0.8 फीसदी सैलेरी में इजाफा हुआ है. एफएमसीजी कंपनियों में भी वेतन केवल 5.4 फीसदी बढ़ा है. प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की हालत बदतर होते जाने का यह भी कारण है कि महंगाई को मिलाकर उनके वेतन को बढ़ने की जगह गिरा हुआ ही कहा जा सकता है. क्योंकि इन कर्मचारियों की खरीदारी की क्षमता में भारी कमी के

संकेत देखे जा रहे हैं. ने कहा, गिरेबां में झांके उद्योग जगतप्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की खराब सैलरी के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आ रही सुस्ती को लेकर भारत सरकार के मुख्य आ. र्थक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने उद्योग जगत को अपने गिरेबां में झांकने के लिए कहा है. दो कॉरपोरेट सम्मेलनों में नागेश्वरन ने कहा कि अगर कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी तो देश को भारी नुकसान हो सकता है. इसका खामियाजा अंततः कॉरपोरेट सेक्टर को भी उठाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि प्रा. इवेट कर्मचारियों के वेतन में अगर सुधार नहीं हुआ तो उनकी खरीदारी की क्षमता घटने से बाजार पर भारी मार पड़ेगी उद्योग के उत्पादों के खरीदने के लिए बाजार में मांग नहीं होगी. यह कॉरपोरेट के लिए आत्मघाती कदम होगा.

रिलायंस ने रूस के रोसनेफ्ट के साथ किया सबसे बड़ा करार , कंपनी रोजाना खरीदेगी 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल

देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (त्म. सपंदबम प्दकनेजतपमे) और रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट (त्वेदमजि) के बीच क्रूड ऑयल (ब्तनकम व्पस) की सप्लाई को लेकर बड़ा करार हुआ है. रॉसनेफ्ट देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को 500,000 (5 लाख) बैरल क्रूड ऑयल प्रति दिन सप्लाई करेगी. क्रूड ऑयल सप्लाई को लेकर दोनों देशों के बीच हुआ अबतक का सबसे बड़ा डील है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की त्वेदमजि के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10 साल के लिए क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए करार किया है जो कि कुल ग्लोबल सप्लाई का 0.5 फीसदी है और क्रूड ऑयल की मौजूदा कीमत के आधार पर ये कुल 13 बिलियन डॉलर की डील है. इस डील के चलते भारत और रूस के बीच एनर्जी सप्लाई को लेकर रिश्तें और मजबूत हा. ेंगे साथ ही रूस को इससे भारी फायदा होगा. क्योंकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमला करने के चलते रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है. त्वेदमजि ने इस डील पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा, वो बाजार के हालात को देखते हुए रूस समेत सभी इंटरनेशनल सप्लायर्स के साथ काम करती है. हालांकि सप्लाई एग्रीमेंट के गोपनीयता को देखते हुए कंपनी ने कमर्शियल मामलों पर इससे ज्यादा कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है. ये डील तब हुआ है जब रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा संभव है. साथ ही रूस के प्रेसीडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे मास्को (डवेबवू) और कीव (ज्ञलपअ) के बीच युद्ध को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं.भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का एक तिमाही रूस से आयात किया जा रहा है. 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय यूनियन ने रूस से तेल आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद भारत रूस ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है. भारत की सरकारी से लेकर निजी तेल कंपनियों ने इंटरनेशनल कीमतों के मुकाबले सस्ते दामों में रूस से क्रूड ऑयल का आयात किया है और उसकी रिफाइनिंग कर पेट्रोल डीजल विदेशों में बेचा है.इस खबर के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज के कारोबारी सत्र में 0.88 फीसदी की गिरावट के साथ 1266 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ा दीजिए गाड़ी, तेल कंपनियों ने जारी की है नई कीमत

देश में तेल बेचने वाली कंपनियों ने 12 दिसंबर 2024 के लिए पेट्रोल डीजल की नई दरें जारी कर दी हैं. ये कंपनियां रा. ेजाना सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतों को जारी करती हैं. पेट्रोल–डीजल का ताजा दाम चेक कर लेने के बाद आपको पेट्रोल पंप का कर्मचारी ठग नहीं पाएगा. देश के चार महानगरों के साथ–साथ झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों के लिए भी कीमतें जारी की गई हैं. हालांकि, दिल्ली और मुंबई सहित देश के चारों महानगरों में आज भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. चार महानगरों में पेट्रोल–डीजल के भावदिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 प्रति लीटर मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपेय प्रति लीटर और डीजल 89.97 रुपये प्रति लीटरक. ेलकाता में पेट्रोल 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटरचेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर बिहार प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के भाव

पेट्रोल की कीमतें

पटनाः 105.53 रुपये प्रति लीटर,मुजफ्फरपुर :105.95 रुपये प्रति लीटर गयाः 105.94 रुपये प्रति लीटर भागलपुरः 106.02 रुपये प्रति लीटर पूर्णिया :106.38 रुपये प्रति लीटर दरभंगाः 106.04 रुपये प्रति लीटर सुपौलः 106.42 रुपये प्रति लीटर पश्चिम चंपारणः106.93 रुपये प्रति लीटर

डीजल की कीमतें

पटनाः 92.37 रुपये प्रति लीटर मुजफ्फरपुरः 92.72 रुपये प्रति लीटरगयाः 92.70 रुपये प्रतिलीटर भागलपुरः 92.81 रुपये प्रति लीटर,पूर्णियाः 93.51 रुपये प्रति लीटर,दरभंगा:92.83 रुपये प्रति लीटर,सुपौलः 93.45 रुपये प्रति लीटर पश्चिम चंपारणः 93.80 रुपये प्रति लीटरझारखंड के प्रमुख जिलों में पेट्रोल डीजल के भाव,पेट्रोल की कीमतें,रांचीः 97.79 रुपये प्रति लीटरजमशेदपुरः 97.73 रुपये प्रति लीटर,धनबादः 97.75 रुपये प्रति लीटर,देवघरः 97.55 रुपये प्रति लीटरबोकारोः 98.04 रुपये प्रति लीटर,डीजल की कीमतें,रांचीः 92.54 रुपये प्रति लीटर,जमशेदपुरः 92.47 रुपये प्रति लीटर धनबादः 92.49 रुपये प्रति लीटरदेवघर :92.24 रुपये प्रति लीटरबो. कारोः 92.78 रुपये प्रति लीटर उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों में पेट्रोल डीजल के भाव,पेट्रोल की कीमतेंआगराः 94.75 रुपये प्रति लीटर लखनऊः 95.10 रुपये प्रति लीटर कानपुर:95.00 रुपये प्रति लीटरइलाहाबाद (प्रयागराज): 95.20 रुपये प्रति लीटर वाराणसीः 95.25 रुपये प्रति लीटरनोएडा:95.30 रुपये प्रति लीटर मेरठः 94.85 रुपये प्रति लीटर

सेबी ने HDFC को जारी की चेतावनी

सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने ने विनियामक निर्देशों का पालन न करने पर HDFC बैंक को चेतावनी जारी की है. भ्क्थ्ब बैंक का कहना है कि गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग में सेबी ने उनके द्वारा विनियामक निर्देशों का पालन न किए जाने की बात कही है. भ्क्थ्ब का कहना है कि हालांकि सेबी की इस चेतावनी का उनकी सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बैंक ने अपने ग्राहकों को भी सेबी की टिप्पणी से संबंधित आवश्यक सुधार किए जाने का आश्वासन दिया है. सेबी (मर्चेंट बैंकर्स) विनियमन, 1992सेबी का यह नियम कंपनी के आईपीओ में अहम भूमिका निभाने वाले मर्चेंट बैंकर्स के लिए है. इसके तहत मर्चेंट बैंकर्स के पंजीकरण, संचालन और जिम्मेदारियों को नियंत्रित किया जाता है. इसके मुताबिक, मर्चेंट बैंकर्स को न केवल आचार संहिता का पालन करना होगा, बल्कि हितों के टकराव से भी बचना होगा.दरअसल, मर्चेंट बैंक के सीनियर अफसर कई बार कंपनी के आईपीओ में बोली लगाते हैं. कई बार अधिकारियों के पास उसी कंपनी के शेयर होते हैं, जिसका आईपीओ वे संभाल रहे हैं. यह हितों में टकराव का मामला है, जिसे सेबी खत्म करना चाहता है. सेबी ने मर्चेंट बैंकर्स को निवेशकों की सुरक्षा सु. निश्चित करने की भी बात कही है.सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 पहले हर कंपनी को सार्वज. निक निर्गम से पहले शेयर बाजारों के पास सुरक्षा जमा के रूप कुछ पैसे रखने पड़ते थे. हालांकि सेबी ने कंपनी के आईपीओ के लिए उपलब्ध निर्गम आकार का एक प्रतिशत नामित शेयर बाजार में जमा करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया.सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015यह विनियम म्यूचुअल फंड कंपनियों के अंदरूनी लोग, जिनमें कंपनी के अधिकारी, ट्रस्टी और उनके करीबी शामिल हैं, उन्हें प्रतिभूति बाजार में व्यापार करने से रोकता है. HDFC बैंक की गैर–बैंकिंग वित्तीय सहायक कंपनी HDBC फाइनेंशियल सर्विसेज ने 12,500 करोड़ रुपये तक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (प्च्व्) के लिए आवेदन किया.

पटना वाले अनिल अग्रवाल की कंपनी ने डिविडेंड देने का किया ऐलान, तो शेयरों ने लगाई छलांग

मेटल और माइन्स क्षेत्र की अनिल अग. ्वाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को निवेशकों को डिविडेंड देने की डेट का ऐलान किया, तो कंपनी के शेयरों ने जोरदार तरीके से छलांग लगा दी. लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को वेदांता लिमिटेड के शेयरों में करीब 2: की उछाल आई. इससे पहले कंपनी ने कहा कि उसका बोर्ड अगले सप्ताह वित्तीय वर्ष 2024–2025 लिए चौथे अंत. रिम डिविडेंड पर विचार करने और उसे स्वीकृत करने के लिए बैठक करेगा.16 दिसंबर को होगी वेदांता बोर्ड की बैठक वेदांता लिमिटेड ने बुधवार को शेयर बा. जारों को दी गई जानकारी में बताया कि उसके बोर्ड की बैठक सोमवार, 16 दि. संबर 2024 को होगी. कंपनी की ओर से जमा कराए गए दस्तावेज में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए इ. क्वटी शेयरों पर चौथे अंतरिम डिविडेंड (यदि कोई हो) पर विचार करने और उसे स्वीकृत करने के लिए सोमवार, 16 दिसंबर, 2024 को निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है. वेदांता लिमिटेड ने डिविडेंड प्राप्त करने के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के लिए मंगलवार, 24 दि. संबर को डेट तय की है.वेदांता के शेयर ने 1 साल में दिया 107: तक मल्टीबैगर रिटन कंपनी की इस घोषणा के बाद वेदांता के शेयर की कीमत गुरुवार की सुबह के कारोबार में 1.8: बढ़कर बीएसई पर 523.70 रुपये पर पहुंच गई और बुधवार के कारोबार में 525.15 रुपये के अपने 52–सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई. सुबह 10 बजे शेयर 1: बढ़कर 519.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था. पिछले एक महीने के दौरान वेदांता के शेयर की कीमत में 13: की तेजी आई है. इस बीच, पिछले एक साल में शेयर ने 107: का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. दिसंबर 2023 में छुए गए 243. 70 रुपये के अपने 52–सप्ताह के निचले स्तर से शेयर में 115: की वृद्धि हुई. मेटल और माइन्स कंपनी वेदांता लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.चौथी बार डि. विडेंड देने जा रही वेदांता

वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक वेदांता ने पहले ही तीन अंतरिम डिविडेंड का भुगतान किया है. इससे पहले मई में 11 रुपये, अगस्त में 4 रुपये और सितंबर में 20 रुपये का डिविडेंड दिया था. अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी ने अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अक्. टूबर में अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए एक बैठक रद्द कर दी थी. ट्रेंडलाइन डेटा के अनुसार, वेदांता लिमिटेड ने 23 जुलाई, 2001 से 45 बार डिविडेंड देने की घोषणा की है. पिछले एक साल में कंपनी ने एक शेयर पर 46 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया, जिससे इसका डिविडेंड यील्ड 8.87: हो गया.

घरेलू–ग्लोबल बाजार में सोना सस्ता, निवेश का भी अच्छा मौका क्योंकि आगे बढ़ेंगे दाम

सोने का भाव एक बार फिर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. इसमें लोकल सर्राफा बाजार में फिर से भाव 80,000 रुपये के करीब जाता दिख रहा है तो क्या आपके लिए खरीदारी का मौका खो गया है? नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि कमोडिटी बाजार में आज सोने के भाव सस्ते मिल रहे हैं और अगर आप निवेश के नजरिए से देख रहे हैं तो यहां पर खरीदारी के लिए अवसर देख सकते हैं. डब् पर कहां पर हैं सोने के दाममल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का भाव आज 788875 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है और इसमें 127 रुपये या 0.16 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. ये सोने का रेट फरवरी कॉन्ट्रेक्ट के लिए है और आज निचले भाव में देखें तो सोना 78755 रुपये तक नीचे गया था. सोने का स्थानीय बाजार का रेट भले ही 79,620 रुपये के आसपास आ गया है लेकिन कमोडिटी मार्केट में आपको सस्ते सोने को खरीदना है तो मौका देख सकते हैं.एमसीएक्स पर चांदी का क्या है भावएमसीएक्स पर चांदी का भाव आज बढ़त के साथ दिखाई दे रहा है और ये 96,000 रुपये के करीब बढ़ रही है. चांदी में 95930 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखा जा रहा है और ये 128 रुपये या 0.13 फीसदी ऊपर कारोबार कर रही है. चांदी की आज की सबसे निचली कीमत 95625 रुपये प्रति किलोग्राम की है.अंत. र्राष्ट्रीय बाजार में कैसी है सोने की कीमत कॉमैक्स पर गोल्ड का फरवरी फ्यूचर्स 2,749.61 डॉलर प्रति औंस पर है और इसमें 7.34 डॉलर या 0.27 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. आज इसमें 2743.49 डॉलर प्रति औंस तक के निचले स्तर देखे गए थे. चांदी की बात करें तो इसमें 0.065 डॉलर प्रति औंस या 0.22 फीसदी की तेजी देखी जा रही है और ये 33.025 डॉलर प्रति औंस के रेट पर मिल रही है. इस तरह साफ है कि ग्लोबल बाजार में भी आज सोने के दाम में गिरावट है और चांदी में तेजी है.आगे चलकर सोने के दाम बढ़ने की उम्मीदस. ीरिया और तुर्की के बढ़ते तनाव और अन्य जियो–पॉलिटिकल तनाव के कारण निवेशक सेफ ऐसेट गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं. इसके चलते सोने में और उछाल आएगा तो अगर आपको सोने में निवेश की रणनीति बनानी है तो कमोडिटी बाजार के जरिए बना सकते हैं.

आवश्यकता है
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र जननायक सम्राट के लिए जिला व्यूरो चीफमंडल व्यूरो चीफ ब्लाक ,ब्यूरो संवाददाता की आवश्यकता है।
सम्पर्क करें –
अमित कुमार वर्मा -संम्पादक
मौः-8218049162,8273402499

जननायक सम्राट
हिन्दी साप्ताहिक
मालिक,मुद्रक, प्रकाशक आरती वर्मा द्वारा आशु प्रिंटिंगप्रेस,अचलताल अलीगढ़ से मुद्रितकराकर . कार्यालय सरोज नगर गली नम्बर 5,अलीगढ़ से प्रकाशित
सम्पादक–अमित कुमार वर्मा
सभी विवाद का न्याय क्षेत्र जनपद अलीगढ़ न्यायलय ही होगा